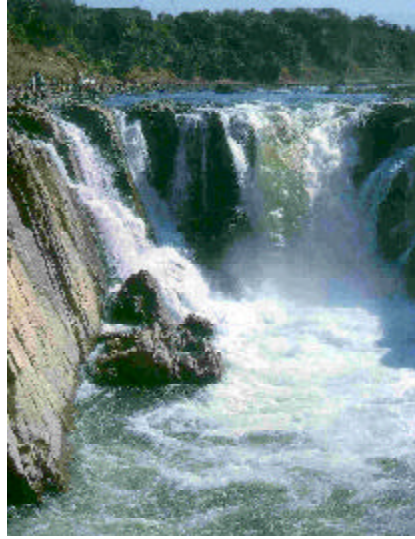


नदियों की बिक्री

डॉ.राम प्रताप गुप्ता बता रहे हैं कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी के नाम पर सरकारें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जल आपूर्ति को निजी क्षेत्र को सौंपकर इस दायित्व से अपना पल्ला झाड़ना चाह रही हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल की आपूर्ति के बहाने पूरी-पूरी नदियां ही बेचना शुरू कर दिया है।

देश में बढ़ती आबादी और जीवन शैली में बदलाव के साथ-साथ पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है। क्या उद्योग, क्या कृषि, क्या घरेलू कार्य, सभी के लिए पानी की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती मांग और स्थिर आपूर्ति की पृष्ठभूमि में उपलब्ध जल स्रोतों पर कब्जे के लिए राज्यों, शहरी एवं ग्रामीण लोगों, संपन्न और गरीब वर्गों, कृषि और औद्योगिक हितों, नदी के ऊपरी और निचले हिस्सों के वासियों के बीच संघर्ष की स्थितियां निर्मित होती जा रही हैं।



इस परिस्थिति में विश्व भर के पूंजीपति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने वाले वर्षों में पानी को मुनाफे के एक बड़े स्रोत के रूप में देख रही हैं। वे चाहती हैं कि विश्व के जल संसाधनों के अधिकतर भाग पर उनका अधिकार हो जाए ताकि वे इसे मनमानी कीमत पर बेचकर अपनी तिज़ोरियां भर सकें। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों ने उनका काम आसान भी बना दिया है।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी के नाम पर सरकारें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जल आपूर्ति को निजी क्षेत्र को सौंपकर इस दायित्व से अपना पल्ला झाड़ना चाह रही हैं। कई राज्य सरकारों ने मात्र शहरी क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति निजी क्षेत्र को सौंपने के कुछ प्रयास किए हैं।

इन सबसे अलग, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल की आपूर्ति के बहाने पूरी-

पूरी नदियां ही बेचना शुरू कर दिया है। इस दिशा में प्रथम प्रयास तो अविभाजित मध्यप्रदेश की सरकार ने ही किया था। सन 1998 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहने वाली शिवनाथ नदी के 23 कि.मी. लंबे हिस्से को कैलाश इंजीनियरिंग की सहयोगी कंपनी रेडियस वाटर को 22 वर्षों के लिए बेच या कहे कि सौंप दिया था। सौंपना शब्द ही अधिक उपयुक्त है क्योंकि बदले में सरकार ने मात्र एक रुपए वार्षिक की लीज़ राशि मांगी थी।

बहाना था कि यह कंपनी नदी के किनारे स्थित उद्योगों को पानी की आपूर्ति करेगी।

सरकार के इस कदम ने इस नदी के किनारे बसे लोगों को इसके पानी के उपयोग से वंचित कर दिया। जिस पानी का ये लोग सदियों से उपयोग कर रहे थे, जिससे अपनी आजीविका चला रहे थे, अचानक ही उनका यह अधिकार छिन गया। रेडियस वाटर का स्वामी बड़े गर्व से नदी के किनारे खड़ा होकर घोषणा कर रहा था कि अगर वह चाहे तो ग्रामवासियों को नदी से पानी लेने, उसमें नहाने-धोने, पशुओं को पानी पिलाने आदि से रोक सकता है और यही उसने किया भी। ग्रामवासियों की नदी तक पहुंच को समाप्त करने के लिए उसने नदी के दोनों ओर पूरे 23 कि.मी. लंबे किनारों पर कंटीले तारों की बागड़ लगा दी। लोगों ने विरोध भी किया, आंदोलन भी चलाया परंतु उदारीकरण के

इस दौर में जन शक्ति को धन शक्ति के आगे हारना ही था। शिवनाथ नदी के 23 कि.मी. क्षेत्र के पानी से रेडियस वाटर कंपनी ने कितना लाभ कमाया, यह देखना भी समयोचित होगा।

नदी के दोनों ओर कंटीले तार लगाने की प्रक्रिया में नदी के किनारे की अत्यंत उपजाऊ 176 एकड़ भूमि पर भी कंपनी ने कब्जा किया जिसका अनुमानित मूल्य 5 करोड़ रुपए है। साथ ही वह शिवनाथ नदी के पानी को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम को बेचकर 1.84 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आय भी अर्जित कर रही है। मात्र एक रुपए की राशि के बदले 500 करोड़ की भूमि पर कब्जा तथा 1.84 करोड़ की वार्षिक आमदनी से अधिक लाभ वाला सौदा शायद ही कोई और हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सार्वजनिक लोक लेखा समिति ने मार्च सन 2007 की रिपोर्ट में शिवनाथ नदी के निजीकरण को राज्य के व्यापक हितों के विरुद्ध बताया था और इसे आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी थी।

ऐसे में यह अपेक्षा की जा सकती थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार नदियों को बेचने की इस नीति को यहीं रोक देगी और आम लोगों के हित एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में कार्य करेगी। परंतु इस समय सरकारों के लिए

आम जनता के हितों का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। वे अब नदियों को ही नहीं, भूगर्भ में स्थित खनिजों, कृषि भूमि आदि को भी उद्योगपतियों को सौंपने की नीति अपना रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार भी लोगों के विरोध और सार्वजनिक लेखा समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद नदियों की बिक्री जारी रखे हुए है। सरकार अब तक केलो, कुरकुट, शबरी, खरम और मांड नदियां बेच चुकी है। यही नहीं, शिवनाथ नदी के दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित निचले भाग को पुनः एस्सार स्टील को बेच दिया है। इस तरह शिवनाथ नदी को एक बार नहीं, दो बार बेचा गया है। प्रचुर वर्षा वाले छत्तीसगढ़ राज्य की प्रचुर प्रवाहित नदियां अब निजी स्वामित्व की वस्तुएं बनती जा रही हैं।

पूंजीपतियों की लाभ की हवस को अब मात्र श्रमिकों के शोषण से संतुष्ट करना संभव नहीं रहा है क्योंकि उत्पादन में प्रयुक्त श्रमिकों की संख्या तो गिरती जा रही है। अतः अब पूंजीपति राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि भूमि, खनिज पदार्थ, वन, पानी आदि पर कब्जा कर अपनी-अपनी तिज़ोरियों को भरने के प्रयासों में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों पर कब्जा भी उन्हीं प्रयासों का अंग है। लोगों को मिल बैठकर सोचना होगा कि इन परिस्थितियों में हमें क्या करना है? (स्रोत फीचर्स)

अगले अंक में

स्रोत अगस्त 2008

अंक 235

● जीन ने बनाया चौपाए से दोपाया

● भारत के प्राचीन वृक्ष

● आखिर क्या है शिलाजीत

● विशुद्ध विज्ञान और व्यावहारिक विज्ञान का समीकरण

● सूक्ष्म विज्ञान के तीन सुनहरे युग

